



सब का सपना



निष्पक्ष व निडर - हिंदी दैनिक समाचार पत्र



ऐसी 5 बीमारियां, जिनके कारण डिप्रेशन में आ जाती हैं महिलाएं **पेज: 7**

मैंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं **पेज: 8**

वर्ष : 02

अंक : 97

शनिवार 11 जुलाई 2026

अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

www.sabkasapna.com

पृष्ठ : 08

मूल्य: 2 रुपए

बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने वापस लिया

नामांकन, सियासी गलियारों में हलचल

बिहार एजेंसी: बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चचाएं तेज हैं। यहां से भाजपा ने अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि, आज बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अपने आप में यह चौकाने वाला फैसला है। इसके पीछे क्या वजह है, इसको लेकर अब तक कोई बात नहीं कही जा रही है। अभिषेक ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को पत्र लिखकर चुनाव नहीं लड़ पाने की जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि कल यानी कि गुरुवार को अभिषेक सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया था।

मोदी का जलवा, न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रखते ही पीएम ने रचा नया इतिहास, दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत



नई दिल्ली एजेंसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छह दिवसीय तीन देशों की सफल यात्रा के अंतिम चरण में शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं हवाई अड्डे पर पहुंच कर किया। चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है क्योंकि यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच तेजी से बदलते सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसंपर्क आधारित संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला महत्वपूर्ण अवसर भी है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब मार्च 2025 में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने आर्थिक

नीति को और मजबूत करेगी तथा महासागर दृष्टि को नई गति देगी। इससे स्पष्ट है कि भारत अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और समावेशी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अपने विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा का सामरिक महत्व अत्यंत व्यापक है। न्यूजीलैंड भले ही आकार में

भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आई थी

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब मार्च 2025 में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने आर्थिक सहयोग के नए द्वार खोल दिए।

समीक्षा भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। गुजरात के लोथल में विकसित हो रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में न्यूजीलैंड की भागीदारी पर भी चर्चा दोनों देशों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सफल यात्रा पूरी कर न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों सहित चौदह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया।

नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौता तथा समुद्री रक्षा सहयोग इस यात्रा की प्रमुख उपलब्धियां रहे। इन सभी पहलों को यदि एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने विश्वसनीय मित्र देशों का मजबूत समूह तैयार कर रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे विश्वास पर आधारित हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल का समुदाय दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत सेतु बन चुका है।

दीपावली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, ओणम, पोंगल और अन्य भारतीय पर्व पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। कथक, भरतनाट्यम, हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति वहां बढ़ती रुचि सांस्कृतिक निकटता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे इसलिए भारतीयों में इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। अनेक सांस्कृतिक बहुरीन विशेष प्रस्तुतियों की तैयारी कर चुके हैं और भारतीय मूल के लोग इसे अपने सम्मान और पहचान से जुड़ा ऐतिहासिक क्षण मान रहे हैं।

बीजेपी का मिशन 2024: एक करोड़ डिजिटल ट्रेड कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य, 12 लाख जुड़े

नई दिल्ली एजेंसी: भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को टेनेन्सालाजी पर आधारित नेटवर्क में बदलने के लिए एक देशव्यापी डिजिटल ट्रेनिंग कैम्पन शुरू किया है। पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रोग्राम में पहले ही 12 लाख से ज्यादा बूथ-लेवल कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महा अभियान' के तहत चलाए जा रहे इस प्रोग्राम का महसुद जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को डिजिटल स्किल्स सिखाया और युवाओं व 'जेन जेड' के साथ बेहतर जुड़ाव के लिए पार्टी को तैयार करना है। बीजेपी ने देश भर के हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने और एक करोड़ डिजिटल रूप से ट्रेड कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है।



बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जो इस प्रोग्राम के को-इन-चार्ज भी हैं, ने एएनआई को बताया कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को इस साल 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन, नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) बी.एल. संतोष और नेशनल को-जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन)

शिव प्रकाश ने लॉन्च किया था। चुग के मुताबिक, इस कैम्पन का शुरूआती लक्ष्य जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस (23 जून) और उनकी जयंती (6 जुलाई) के बीच 10 लाख कार्यकर्ताओं को शामिल करना था। हालांकि, इस दौरान इसमें शामिल होने वालों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई। एक ऐप-

आधारित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए, कार्यकर्ताओं को स्टडी मटीरियल, टॉपिक-वाइज वीडियो और विक्ज का इस्तेमाल करके 12 भाषाओं में ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इस ट्रेनिंग में इखद का इतिहास, विचारधारा, संगठनात्मक सिद्धांत, 'पंच निष्ठा', डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और उनकी शिक्षाएं, साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें 'मन की बात' और पार्टी के बड़े आउटरीच अभियानों सहित प्रमुख संगठनात्मक कार्यक्रमों से परिचित कराया जाता है।

नई दिल्ली एजेंसी: देश में ई20 (20% एथिल अल्कोहल मिश्रित) पेट्रोल की अनिवार्य उपलब्धता के खिलाफ वाहन चालकों ने बिना मिश्रण वाले सादे पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार देने की अपील की गई है। वाहन चालकों और विशेषज्ञों का दावा है कि ई20 ईंधन से पुराने वाहनों के इंजन, पाइपलाइन और माइलेज पर बुरा असर पड़ रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए ऑटोमोबाइल निमाताओं से स्थिति स्पष्ट करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की है।



सरकार जहां पर्यावरण और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एथॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है, वहीं यह विवाद नीति बनाम उपभोक्ता सुरक्षा की जंग बन गया है। ग्राहक रेगुलर पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रीमियम प्म्यूल की बढ़ती मांग के पीछे अप्रैल 2025 में पूरे भारत में ई20 पेट्रोल को लागू करने की योजना है। सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने, गाड़ियों से

होने वाले प्रदूषण को घटाने और खेती से मिलने वाले कच्चे माल से इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने की अपनी रणनीति के तहत, तय समय से कई साल पहले ही 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। हालांकि सरकार का हमेशा से यही कहना रहा है कि ई20 पेट्रोल उन गाड़ियों के लिए सुरक्षित है जिन्हें इसके इस्तेमाल के लिए बनाया या मंजूरी दी गई है, फिर भी पुरानी पेट्रोल

कारों और दोपहिया वाहनों के कई मालिक इसके लंबे समय तक पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। कई ग्राहकों का मानना है कि इथेनॉल-मिला पेट्रोल गाड़ियों की माइलेज (प्म्यूल एफिएसई) पर बुरा असर डालता है। चूंकि आम पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, इसलिए गाड़ी चलाने वालों का कहना है कि पूरे देश में इस बदलाव के बाद उन्हें माइलेज में साफ कमी महसूस हुई है। क्या ई20 का असर पुरानी गाड़ियों पर पड़ रहा है? माइलेज की चिंता के अलावा, इथेनॉल की नमी सोखने की क्षमता (हाइग्रोस्कोपिक नेचर) के कारण लंबे समय तक इस्तेमाल से प्म्यूल सिस्टम में जंग लगने का डर भी पैदा हो गया है।

मैंने पुलिस पर भरोसा किया, उन्होंने ही, सीएम विजय ने करुण रासदी के घाव को किया याद, बोले- यह दर्द कभी नहीं भूलेंगे

नई दिल्ली एजेंसी: करुण में मची भगदड़, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और जिसका असर राज्य विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा था, उसके नौ महीने बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय श्रुक्वार को शहर लौटे। उन्होंने इस त्रासदी में अपनी भूमिका का बचाव किया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पिछली DMK सरकार पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री के तौर पर करुण के अपने पहले दौर पर पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए, विजय ने भावुक होकर उस त्रासदी को याद किया और कहा कि उन नुकसान का बोझ आज भी उनके मन पर भारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करुण के दौरे पर आए उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, मानसिक रूप से कुछ ऐसे घाव और चोटें होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम कई तरह की चोटों और घावों से उबरकर ही यहां तक



पहुंचे हैं। लेकिन इन सबसे बुरा, वह घाव और दर्द जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वह करुण की घटना थी। विजय ने कहा कि पिछले साल करुण का उनका दौरा टीवीके के लोगों तक पहुंचने और उनकी समस्याओं के बारे में आवाज उठाने का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि अरियालुर में एक मीटिंग खत्म करने के बाद परम्बलुर पुलिस ने उन्हें वहां जमा भारी भीड़ के बारे में अगाह किया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बताया गया था कि देर हो रही है और उन्हें वहां नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब पुलिस हमें कुछ कहती है, तो हमें उनकी बात माननी

ही पड़ती है, है ना? साथ ही, परम्बलुर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम भारी मन से वापस लौट आए। विजय ने अपनी पार्टी पर मौतों का आरोप लगाते हुए इसे खारिज कर दिया और तर्क दिया कि भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी पुलिस की थी। अभिनेता से नेता बने विजय ने कहा कि मैंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पर भरोसा किया था, फिर भी मुझे मौतों के लिए दोषी ठहराया गया। रैली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टीवीके प्रमुख ने कहा कि अधिकारी बिगड़ती स्थिति के बारे में उनकी टीम को सूचित करके इस त्रासदी को रोक सकते थे।

बीच सुनवाई पहले जज पर फेंके कागज, फिर गाली देते हुए बोला- इसे सीजेआई को दे देना, सुप्रीम कोर्ट में हाई-वोल्टेज झगडा

नई दिल्ली एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय हालात देखने को मिले, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान, खुद पेश हुए एक शिकायतकर्ता ने बेंच की तरफ कागजात फेंके और अपशब्द कहे। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। यह घटना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने हुई। कोर्ट रूम का माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब याचिकाकर्ता ने जजों से बात करते हुए असामान्य रूप से आक्रामक लहजा अपनाया। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों की शुरुआत में कहा कि अक्रामक लहजा अपनाया। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों की शुरुआत में कहा कि अक्रामक लहजा अपनाया। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों की शुरुआत में कहा कि अक्रामक लहजा अपनाया। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों की शुरुआत में कहा कि अक्रामक लहजा अपनाया।

विश्वनाथन ने पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं? कोर्ट में जवाब देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लाइव लॉ के अनुसार, इसके कुछ ही देर बाद मामला तब और बढ़ गया जब याचिकाकर्ता ने अपने केस के कागजात हवा में उछाल दिए और आरोप है कि चीफ जस्टिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत दखल दिया और उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकालकर स्थिति को सामान्य किया। इस पूरी घटना के दौरान बेंच शांत रही और उसने इस गुस्से भरी प्रतिक्रिया पर कोई जवाब नहीं दिया। यह घटना इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई।

भारी वर्षा से उड़ान कैसिल, सड़क से मुश्किल, पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, सियासी बैठकें अहम

नई दिल्ली एजेंसी: भारी बारिश के कारण मुश्किलदा बाढ़ जाने वाली अपनी तय फ्लाइट रद्द करनी पड़ने पर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सड़क मार्ग से यात्रा की। पद संभालने के बाद मुश्किलदा बाढ़ का यह उनका पहला दौरा है। अधिकारी बहरामपुर के एक होटल में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद रवींद्र सदन में प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। दिन में बाद में, वह रेजीनगर में पार्टी की एक सभा को संबोधित करेंगे। आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक और नौदा के विधायक हुमायूँ कबीर की हालिया टिप्पणियों के बाद यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से काफी अहम है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी मॉनसूनी बारिश हुई; शुक्रवार सुबह खसम हुए 24 घंटों में कूचबिहार में राज्य की सबसे ज्यादा 143 मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण उड़ान भरना



असुरक्षित हो गया था, इसलिए अधिकारी के यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अधिकारी ने कहा हमने विपक्ष के नेता के हवाई यात्रा करने की योजना बनाई थी। लेकिन लगातार बारिश और मौजूदा मौसम की वजह से हवाई यात्रा करना मुश्किल नहीं हो पाया। हालात का जाहजा लेने के बाद यह तय किया गया कि वे सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। इसके लिए सभी जरूरी सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजाम किए गए। रेजीनगर के कार्यक्रम ने राजनीतिक ध्यान खींचा है क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र हुमायूँ कबीर का गढ़ माना जाता है, जो हाल ही में

कथित भड़काऊ बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान, अधिकारी ने कबीर पर आरोप लगाया कि वे उपचुनाव से पहले वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यह उपचुनाव एजेयूपी नेता के रेजीनगर सीट छोड़ने के बाद होने की उम्मीद है, जिस पर उनके बेटे के चुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि, कबीर का कहना था कि उनकी टिप्पणी राज्य सरकार के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जो विधानसभा चुनाव के बाद मुश्किलदाबाद में बीजेपी में शामिल हुए थे और कथित तौर पर उन्हें धमका रहे थे।

असम बजट: 10 साल में 10 गुना बढ़ा पूंजीगत व्यय, मुख्यमंत्री हिमंत बोले- संकल्प पत्र पूरा करेंगे

असम एजेंसी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि 2026-27 का राज्य बजट बीजेपी सरकार के "संकल्प पत्र" को दिखाता है। इसमें कैपिटल खर्च में भारी बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और बिजली के क्षेत्र में बड़े निवेश के साथ-साथ कल्याण, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। असम विधानसभा के बजट सत्र (जो 6 जुलाई को शुरू हुआ था) के दौरान राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा 2026-27 का

बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि पिछले दस सालों में राज्य का कैपिटल खर्च लगभग दस गुना बढ़ गया है। 2015-16 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूँजीगत खर्च) 2,951 करोड़ रुपये था। इस बजट में यह बढ़कर लगभग 29,000 करोड़ रुपये हो गया है। हमने अलग-अलग सेक्टर में टैक्स में छूट का प्रस्ताव दिया है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर 'ग्रीन सेस' लगाने का प्रस्ताव है और इसका इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज और ग्रीन पहलों के लिए किया जाएगा। यह बजट हमारे



'संकल्प पत्र' को दशर्ता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य दो लाख नौकरियां देना है और भर्ती प्रक्रिया को देखरेख के

लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। हम दो लाख नौकरियां देंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स

बनाई गई है। अगस्त से सभी जनकल्याण योजनाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। हम प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं पर 6,000 करोड़ रुपये

असम विधानसभा के बजट सत्र (जो 6 जुलाई को शुरू हुआ था) के दौरान राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ द्वारा 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि पिछले दस सालों में राज्य का कैपिटल खर्च लगभग दस गुना बढ़ गया है।

खर्च करेंगे। शर्मा ने यह भी घोषणा की कि एक से ज्यादा शादियां करने वाले पुरुष और आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने की कोशिशों का हिस्सा है। बुनियादी ढांचे के बारे में

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'असम माला 4.0' के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, सिलचर में डोलू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और रूपसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि डोलू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। बजट में बिजली

क्षेत्र में 77,353 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है और प्रस्तावित 'न्यू गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी' के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी कुल जमीन अधिग्रहण लागत 6,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी पहलों का ज़िफ़ करते हुए शर्मा ने कहा कि असम का लक्ष्य 2030 तक 2,300 डॉक्टर तैयार करना और हर हेल्थ सब-सेंटर में एक डॉक्टर तैनात करने वाला पहला राज्य बनना है। उन्होंने दो आधुनिक इंटीग्रेटेड एकेडमिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना की भी घोषणा



संपादकीय

सरकारी से मोहभंग

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। दृष्टानुपाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस६ के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023-24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025-26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है। दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र-शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है।

चिंतन-मनन

भगवान की विचारणाएं

जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं और पैदा हुआ हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? भगवान द्वारा सोचना, विचारना, बोलना, भावनाएं आदि अमानतें मनुष्य को इसलिए नहीं दी गई हैं कि उनके द्वारा वह सुख-सुविधाएं या विलासिता के साधन जुटा अपना अहंकार पूरा करे बल्कि इसलिए दी गयी हैं ताकि इनके माध्यम से वह विश्व की अधिक सुन्दर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न कर। बैंक के खजांची के पास धन इसलिए रखा रहता है ताकि सरकारी प्रयोजनों के लिए इस पैसे को खर्च कर। खजाने में रखे लाखों रुपये खजांची कैसे खर्च कर सकता है।अपने लिए उसे उतना ही इस्तेमाल करने का हक है, जितना उसे वेतन मिलता है। पुलिस और फौज का कमांडर है, उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं, उसी से काम चलाना चाहिए। बाकी बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति उसे बंदूक चलाने के लिए मिली है, उसे सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने उसको सौंपा है। हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ विभूतियां, अक्ल और विशेषताएं हैं, वे व्यक्तिगत ऐय्याशी सुविधा और शौक-मौज के लिए नहीं हैं। व्यक्तिगत अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं है। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है- निरुस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को इतना ज्यादा प्यार किया। मनुष्य को उस तरह का मस्तिष्क दिया है, जितना कीमती कम्प्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। मनुष्य की आंखें, कान, नाक, वाणी एक से एक चीजें हैं, जिनकी रुपयों में कीमत नहीं आंकी जाती है। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है, जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्योछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य जिस भगवान ने बनाया है, उसकी यह आकांक्षा जरूर रही है कि दुनिया को समुन्नत और सुखी बनाने में यह प्राणी मेरे सहायक के रूप में काम करेगा और मेरी सृष्टि को समुन्नत रखेगा। मानव जीवन की विशेषताओं और भगवान द्वारा विशेष विभूतियां मनुष्य को देने का एक और उद्देश्य है। जब मनुष्य इस जिम्मेदारी को समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं और पैदा हुआ हूं तो मुझे क्या करना चाहिए।ट तो समझना चाहिए कि इस आदमी का नाम मनुष्य है, इसके भीतर मनुष्यता का उदय हुआ और इसके अंदर भगवान की विचारणाएं उदित हो गयीं।

आवश्यकता है

आवश्यकता है दैनिक सब का सपना समाचार पत्र को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर व जिला स्तर पर संवाददाताओं की इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।

9456884327/8218179552



प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है- 'युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साकार करना-आज और भविष्य के लिए।' यह विषय स्पष्ट संकेत देता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या के आकार से नहीं, बल्कि उस जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अवसरों से निर्धारित होता है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह स्थिति एक ओर विशाल मानव संसाधन का अवसर प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस भारत के लिए केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि गंभीर आत्ममंथन का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक अवसरों पर छोटे परिवार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जो परिवार स्वेच्छा से परिवार नियोजन अपनाते हैं, वे राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनका यह संदेश बताता है कि जनसंख्या संतुलन किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश के सतत विकास का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने भी समय-समय पर यह कहा है कि जनसंख्या नीति सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए तथा इसका उद्देश्य किसी समुदाय को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित, संसाधनों के संतुलित उपयोग और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करना होना चाहिए।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र



भारत की राजनीति में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है, जो जब भी सामने आता है, अपने साथ बहसों का एक नया दौर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में इसे लागू किए जाने के बाद, अब देश के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवागिर्वृत्त जज रंजन प्राशाद देसाई की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सरकार की कोशिश है कि आगामी सत्रों में ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया जाए। लेकिन क्या देश के सबसे अधिक सामाजिक और आर्थिक विविधता वाले राज्यों में से एक में इसे लागू करना इतना सीधा रास्ता है ? या फिर

नक्सलवाद के बाद घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार, अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूँका

देश को नक्सल आतंक की जकड़ से बाहर निकालने और जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अगले चरण का बिगुल फूँक दिया है। इस बार निशाने पर केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि घुसपैठ के जरिये सीमावर्ती इलाकों में बदलता जनसंख्या संतुलन, तस्करी, मादक पदार्थों का जाल, कट्टरपंथ, ड्रोन खबरे, संगठित अपराध और सीमा पार से संचालित छद्म युद्ध की पूरी रणनीति है। अमित शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने और सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच देने का व्यापक अभियान अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अमित शाह का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन केवल स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऐसे में यह अभियान वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के भारत की सुरक्षा का भी मजबूत आधार बनेगा। हम आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीमा सुरक्षा के लिए सरकार की नई और व्यापक रणनीति सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल भूमि सीमाओं तक ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी इसी प्रकार का समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सम्मेलन में सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों, उनके समाधान और भविष्य की नीति तैयार करने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था अब केवल चौकियों और गश्त तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार सीमा सुरक्षा बलों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को साथ जोड़कर चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र तैयार कर रही है। यही चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भविष्य में भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। गृह मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत की लगभग पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा

तभी पूरी तरह साकार हो सकता है, जब विकास की गति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हो। यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ती रहे और संसाधनों का विस्तार उसी अनुपात में न हो, तो विकास की उपलब्धियां भी पर्याप्त सिद्ध नहीं होंगी। रोजगार के अवसर सीमित होंगे, कृषि योग्य भूमि सिकुड़ेगी, जल संकट गहराएगा, महानगरों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर होता जाएगा। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या संबंधी विमर्श तथ्यों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव पर आधारित हो। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है और जनसंख्या नीति का उद्देश्य भी समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू होने वाला, न्यायसंगत एवं पारदर्शी ढांचा होना चाहिए। परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, विवाह की उपयुक्त आयु, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जन-जागरूकता ऐसे उपाय हैं, जिनसे बिना किसी भेदभाव के जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व के अनेक अनुभव बताते हैं कि जैसे-जैसे शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और आर्थिक विकास बढ़ता है, वैसे-वैसे प्रजनन दर स्वाभाविक रूप से घटती है। भारत के सामने एक अन्य गंभीर चुनौती अवैध घुसपैठ की भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यदि अवैध रूप से लोगों का प्रवेश होता है और वे बिना वैधानिक प्रक्रिया के देश में बस जाते हैं, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों के वितरण तथा जनसांख्यिकीय संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय जनसंख्या नियंत्रण से अलग, कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। अतः सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, अवैध प्रवासन पर प्रभावी नियंत्रण रखना तथा नागरिकता संबंधी कानूनों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह मुद्दा किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। भारत को यह भी समझना होगा कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। चीन ने अपने समय में एक-संतान नीति अपनाई, लेकिन बाद में बदलती परिस्थितियों के कारण उसे वापस लेना पड़ा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन से भिन्न है। इसलिए भारत के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग वह होगा जिसमें कानून

समान नागरिक संहिता: कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात?

इस कदम की टाइमिंग के पीछे चुनावी समीकरणों की कोई गहरी बिसात बिछी है ? जब हम सरकार के इस फैसले को बारीकी से देखते हैं, तो इसके दोनों पहलुओं को निष्पक्षता से तौलना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके समर्थक इसे संविधान के अनुच्छेद 44 में दर्ज नीति निर्देशक तत्वों के तहत एक राष्ट्र, एक कानून के सपने को सच करने की दिशा में एक साहसिक कदम मानते हैं। उनका तर्क है कि शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा और सदियों पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। इस संहिता की कमान जस्टिस रंजना देसाई को सौंपना प्रशासनिक रूप से एक सोची-समझी रणनीति दिखती है, क्योंकि उन्होंने ही पहले उत्तराखंड के कानून का मसौदा तैयार किया था। उनके इस तकनीकी अनुभव का लाभ महाराष्ट्र सरकार उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अतीत में शाह बानो और सरला मुद्दल जैसे ऐतिहासिक मामलों में देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बल दिया है, जिससे इस विचार को संवैधानिक मजबूती मिलती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर और वास्तविक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसी सीमित

समान नागरिक संहिता: कानूनी सुधार की नीयत या राजनीतिक बिसात?



अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों के भरोसे पसंच नहीं है। इसके लिए स्थानीय समाज की भागीदारी, प्रशासनिक समन्वय और आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग अनिवार्य है। इसी सोच के तहत सरकार अलग थलग सीमा चौकियों की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर एकीकृत सुरक्षा तंत्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की स्पष्ट सीमा की परिकल्पना आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे आधुनिक सीमा सुरक्षा व्यवस्था का रूप लेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में हिंसा के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब अगले तीन वर्षों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी निर्णायक प्रहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिससे देश पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बने और भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले समस्याएं स्थानी होती थीं और समाधान अस्थायी, लेकिन अब सरकार समस्याओं की जड़ पर प्रहार कर स्थायी समाधान तैयार कर रही है।

देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलते जनसंख्या स्वरूप पर मोदी सरकार का विशेष ध्यान है। अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण अवैध घुसपैठ है। इसी कारण प्रधानमंत्री

के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, स्वेच्छिक सहभागिता, शिक्षा और सकारात्मक प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी जाए। छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। पिछले एक वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.19 अरब से बढ़कर 8.30 अरब हो गई है, अर्थात एक वर्ष में लगभग 6.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो लगभग 0.83 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या 1.45 अरब से बढ़कर लगभग 1.47 अरब हो गई है, यानी एक वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ लोग और जुड़ गए। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.87-0.89 प्रतिशत के बीच है, जो वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक है। भारत विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इतनी विशाल जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, ऊर्जा, कृषि भूमि और पर्यावरण पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि जनसंख्या वृद्धि और विकास के बीच संतुलन नहीं बनाया जा सके, तो विकास की नींव कमजोर होगी। इसलिए केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव संसाधन विकास और संसाधनों के संतुलित नियोजन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। भारत में जनसंख्या का प्रश्न केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी विषय बन गया है। जातिगत जगणगीता और विभिन्न जाति-समुदायों की जनसंख्या को लेकर राजनीतिक दल अक्सर अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। अनेक विशेषकों का मानना है कि यदि जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण या चुनावी लाभ के लिए किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास की भावना के विपरीत होगा। इसके विपरीत, चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप लंबे समय तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया, यद्यपि बाद में बदलती जनसांख्यिकीय चुनौतियों के कारण उसने उस

आबादी वाले राज्य और महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी आदिवासी आबादी है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं, प्रथाएं और सामाजिक नियम हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल अल्पसंख्यक समुदाय और अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों का एक बेहद पेचीदा ताना-बाना है। इतने बड़े और विविधता से भरे राज्य में बिना किसी व्यापक सामाजिक संवाद के, केवल छह महीने के भीतर एकतरफा मसौदा तैयार कर लेना जमीनी सच्चाइयों से आंखें मूंदने जैसा हो सकता है।

भारत का संविधान जहां एक तरफ समानता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना किसी भी कानूनिवद के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। एक ओर बड़ा सवाल इस संहिता में पूर्व जजों, पूर्व मुख्य सचिव और संवैधानिक विशेषज्ञों को तो जगह मिली है, लेकिन अल्पसंख्यक या आदिवासी समुदायों के जमीनी प्रतिनिधियों की कमी साफ खलती है। जब आप समाज के हर वर्ग के निजी जीवन को प्रभावित करने वाला कोई बड़ा कानून बनाने जा रहे हों, तो उस चर्चा की मेज पर सभी पक्षों की मौजूदगी न होना कानून की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े करता है। कानून ऐसा होना

नीति में संशोधन भी किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग है, इसलिए यहां समाधान कठोर दमनात्मक उपायों के बजाय समान रूप से लागू होने वाली जनसंख्या नीति, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, परिवार नियोजन, जन-जागरूकता और कानून के निष्पक्ष अनुपालन में निहित है। जनसंख्या के प्रश्न को जाति, धर्म या वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के हित के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम भी इसी दिशा में संकेत करती है कि यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिलेंगे, तो वे स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनकर संतुलित परिवार और सतत विकास की दिशा में योगदान देंगे। भारत की लगभग आधी आबादी युवा है। यह जनसं-ख्यिकीय लाभांश तभी राष्ट्र की शक्ति बनेगा, जब यह जागरूक, कुशल, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा। अन्यथा यही विशाल युवा आबादी बेरोजगारी, असंतोष और सामाजिक चुनौतियों का कारण भी बन सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक व्यापक, वैज्ञानिक और सर्वसम्मत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर गंभीर विचार किया जाए। ऐसी नीति में समानता, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही जनसंख्या संबंधी किसी भी चर्चा में सामाजिक सीाहार्द, तथ्यपरक विश्लेषण और जिम्मेदार सार्वजनिक विमर्श बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या विभाजनकारी दृष्टिकोण समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह स्मरण कराना है कि विकसित भारत का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, मानव पूंजी में निवेश, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, प्रभावी सीमा प्रबंधन और दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति-इन सभी का समन्वित प्रयास आवश्यक है। यदि भारत समय रहते जनसंख्या संतुलन, मानव विकास और संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का लक्ष्य अधिक यथार्थ रूप में साकार हो सकेगा।

चाहिए जो समाज के हर तबके को अपना सा लगे, न कि किसी पर थोपा हुआ महसूस हो। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम की टाइमिंग पर भी लगातार उलगी उठा रहे हैं। यह सवाल उठना लाजिमी है कि देश या राज्य में जब भी कोई बड़ा चुनाव नजदीक आता है या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले होते हैं, तभी समान नागरिक संहिता जैसे भावनात्मक मुद्दों को तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जाता है ? अगर मंशा सचमुच केवल कानूनी और सामाजिक सुधार की है, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर जन-सुनवाई क्यों नहीं की जाती ? सभी हितधारकों, धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से खुलकर चर्चा करने में आखिर क्या हिचक है ? समान नागरिक संहिता अपने आप में एक प्रगतिशील और आधुनिक विचार हो सकती है, बशर्ते उसे सुधार की सच्ची नीयत से लाया जाए, न कि किसी राजनीतिक लाभ या ध्रुवीकरण के लिए। भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में कोई भी नागरिक कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। यदि महाराष्ट्र सरकार वाकई इस दिशा में कोई सार्थक और ऐतिहासिक बदलाव करना चाहती है, तो उसे जल्दबाजी छोड़कर इस कानून को सर्वसम्मति, पारदर्शिता और बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के आगे बढ़ाना होगा। अन्यथा, यह कदम भी एक वास्तविक विचार सुधार बनने के बजाय केवल एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा। (लेखक पत्रकार हैं)

कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम गांव को पहला गांव बताया है। इस योजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार का मानना है कि जब सीमा पर बसे गांव समृद्ध होंगे, वहां के लोग सुरक्षित और आत्मनिर्भर होंगे, तभी सीमा सुरक्षा भी स्थायी रूप से मजबूत होगी।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह नई नीति भारत की सुरक्षा सोच में बड़ा परिवर्तन है। अब देश केवल किसी घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं रहेगा, बल्कि संधावित खतरों को पहले ही पहचानकर उधे रोकने की सक्रिय रणनीति अपनाई जाएगी। घुसपैठ, छद्म युद्ध, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिये हथियार पहुंचाना, साहजर अपराध और संगठित अपराध आज एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। ऐसे में इन सभी के खिलाफ एकीकृत सुरक्षा तंत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन की निगरानी, आधुनिक तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था और सीमावर्ती गांवों का विकास एक साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो भारत ने केवल अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाहरी चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में भी होगा। अमित शाह द्वारा प्रस्तुत यह नई रणनीति केवल सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, सामरिक शक्ति और भविष्य के भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने वाला व्यापक अभियान बनकर उभर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए अमित शाह स्वयं भी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सीमा चौकियों का निरीक्षण किया, सुरक्षा बलों के साथ संवाद स्थापित किया, नियंत्रण रेखा का निरीक्षण किया, भारत-पाक सीमा के अत्यंत संवेदशील क्षेत्र जाकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और महिला जवानों के लिए नई बैरकों का उद्घाटन किया। स्पष्ट है कि मोदी सरकार केवल नीतियां बनाते तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, तकनीक आधारित सुरक्षा तंत्र, मजबूत समन्वय और प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे सीमा सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।



सीबीआरसेटी में जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर बैच का शुभारंभ, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी युवतियां



बहजोई/संभल (सब का सपना):– जनपद के बहजोई स्थित केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआरसेटी) में शुक्रवार को जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान की संकाय मानसी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रशिक्षार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें प्रशिक्षण के उद्देश्य और स्वरोजगार की

संभावनाओं से अवगत कराया गया। संकाय मानसी शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में ब्यूटी एवं वेलनेस उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है और इस क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान का लक्ष्य युवाओं, विशेषकर महिलाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के



दौरान प्रतिभागियों को हैयर कटिंग एवं स्टाइलिंग, स्किन केयर, फेशियल, मेकअप, मेहंदी, ब्यूटी थैरेपी, ग्राहक व्यवहार, व्यवसाय प्रबंधन तथा स्वरोजगार स्थापित करने से जुड़े व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों से नियमित

उपस्थिति, अनुशासन और पूरी लगन के साथ प्रशिक्षण लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर संकाय संतोष कुमार, कार्यालय सहायक सुजीत सिंह, विशेष, डीएसटी मीरा, रीता कुमारी सहित संस्थान के अन्य कर्मचारी एवं सभी प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के शुभारंभ को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

यातायात जागरूकता अभियान चलाकर बारिश में सुरक्षित ड्राइविंग के बताए गए नियम



बहजोई/संभल (सब का सपना):– पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिस्नोई के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी यातायात एवं प्रभारी यातायात जग रेशन सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को कस्बा बहजोई में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को वर्षा ऋतु में सुरक्षित वाहन संचालन के संबंध में

महत्वपूर्ण जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। मुख्य आरक्षी सोनू अहलावत ने वाहन चालकों को बताया कि बारिश के दौरान वाहन की गति नियंत्रित रखें, अचानक ब्रेक लगाने से बचें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें तथा जलभराव वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतें।



दोपहिया वाहन चालकों से आईएसआई मार्क हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की अपील की गई। इस दौरान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा सभी यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को

जागरूक किया गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से स्वयं नियमों का पालन करने के साथ-साथ दूसरों को भी जागरूक करने की अपील करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

एबीवीपी के स्थापना दिवस पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, मेडल व प्रशस्ति पत्र किए वितरित

चंदौसी/संभल(सब का सपना):– अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जिला सम्भल नगर इकाई चंदौसी द्वारा परिषद के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित विद्यार्थियों में कक्षा 9 के आकाश, वंशिका चौहान और प्रतीक्षा, कक्षा 10 के नितेश, गौरव और अमन कुमार, कक्षा 11 के अंश शर्मा, अमन और तरुण कुमार तथा कक्षा 12 के विशाल, बंटी मीणा और प्रियांशु प्रजापति शामिल रहे। मुख्य अतिथि सिद्धार्थ स्वामी ने कहा



कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, परिश्रम और संस्कार सफलता की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आदर्श नागरिक बनने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भोपाल सिंह शास्त्री ने कहा कि प्रतिभा तभी सार्थक होती है जब

शक्ति मानते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है। प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य छात्रों का उत्साहवर्धन कर उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री दिवाकर बावरा, जिला प्रमुख पंकज शर्मा, हयातनगर नगर अध्यक्ष डिंपल वाघेण्य, जिला संयोजक अखिलेश श्रीवास्तव, नगर मंत्री आशीष कुमार, शोएब, रवि दिवाकर सहित परिषद के पदाधिकारी, विद्यालय परिवार एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ तथा सभी सम्मानित विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं।

लगातार बारिश में मकान की छत गिरने से बुजुर्ग गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर

बहजोई/संभल (सब का सपना):– लगातार हो रही बारिश के बीच शुक्रवार सुबह थाना धनारी क्षेत्र के ग्राम करेला की मड़ैया में एक बड़ा हादसा हो गया। मकान की जर्जर छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से घर में मौजूद 65 वर्षीय बुजुर्ग संतोगी पुत्र करन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों व ग्रामीण तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बहजोई



लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सिर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट होने के कारण उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए

अचानक छत गिरने से यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि उस समय घर के अन्य सदस्य छत की चपेट में नहीं आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल का प्राथमिक उपचार कर आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेज दिया गया। घटना के बाद गांव में भी हादसे को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों के लिए यह घटना एक गंभीर चेतावनी मानी जा रही है।

पुलिस ने मोबाइल लूट गिरोह का किया पदार्पाश, दो बदमाश गिरफ्तार

बनियाठेर/संभल (सब का सपना):– थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए गिरोह के दो वांछित बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा लूट की रकम बरामद की गई है। वहीं गिरोह का एक अन्य सदस्य पहले ही चंदौसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई को ग्राम गुमथल निवासी हरिओम प्रजापति पुत्र सीताराम ने थाना बनियाठेर में तहरीर देकर बताया था कि मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इस संबंध में थाना बनियाठेर पर बीएनएस के तहत



मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि यही गिरोह थाना चंदौसी क्षेत्र में भी तीन मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन घटनाओं के संबंध में थाना चंदौसी में मामला दर्ज किया गया था। चंदौसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को गिरोह के सदस्य विजय उर्फ कम्प्यूटर पुत्र छोटे लाल को गिरफ्तार

नन्दे उर्फ भगतजी को गिरफ्तार कर लिया। तलाश के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक अवैध 12 बोर तमंचा, दो जिंदा कारतूस तथा 2,750 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों से मोबाइल लूट की घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में लूट और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मालन नदी पर हाई अलर्ट, लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर, सिंचाई विभाग सतर्क, तटबंधों की निगरानी तेज

बिजनौर (सब का सपना):– जनपद में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में जारी वर्षा के चलते मालन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नदी किनारे स्थित तटबंधों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। विभागीय टीमों मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहाड़ों से लगातार पानी आने के कारण मालन नदी का जलस्तर आगामी घंटों में और बढ़ सकता है। इसी को ध्यान

में रखते हुए विभागीय कर्मचारी संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिए गए हैं और तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। उधर, गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार बुधवार को गंगा में लगभग 26 हजार क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था, जो गुरुवार तक बढ़कर 79 हजार क्यूसेक पहुंच गया। महज 24 घंटे में जलप्रवाह लगभग तीन गुना बढ़ने से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी पंकज जैन ने यूसुफपुर-बाखरपुर तटबंध का निरीक्षण कर उसकी

स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि तटबंध फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एहतियातन हाई अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग की टीमें हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मालन नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया था। हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना

पड़ा था। इतना ही नहीं, मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई दिनों तक बंद रहा था और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से ही पूरी सतर्कता बरत रहा है। सिंचाई विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से भी अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाएं, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

समय रहते रुका बाल विवाह, नाबालिग किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया

बहजोई/संभल (सब का सपना):– जनपद में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस की तत्परा से एक नाबालिग किशोरी का बाल विवाह होने से रोक दिया गया। शनिवार 11 जुलाई को होने वाले इस विवाह की सूचना मिलते ही पुलिस, बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवाया तथा किशोरी को संरक्षण में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिस्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी का विवाह तय होने की सूचना बाल विवाह रोकथाम के क्षेत्र में कार्यरत जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था प्रयत्न को मिली। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना बहजोई एवं एएचटी (एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग) इकाई को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाहक प्रभारी उप निरीक्षक बाबू



राम सेनी के नेतृत्व में गठित टीम मौके पर पहुंची और किशोरी के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच की। जांच में किशोरी के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर टीम ने तत्काल बाल विवाह रोकना दिया। टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी कि यदि बाल विवाह कराया गया तो इसमें शामिल सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाह कराने वाले पंडित, नाई, हलवाई, टेंट संचालक सहित

आयोजन में सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति कानून के दायरे में आएंगे। कार्रवाई के बाद किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे सुरक्षा एवं देखभाल के लिए एन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। चाइल्डलाइन की टीम ने किशोरी की काउंसलिंग कर उसे उसके अधिकारों और भविष्य की शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस

हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1800-102-7222 पर सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इस दौरान कार्यवाहक प्रभारी उप निरीक्षक बाबू राम सेनी, प्रयत्न संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी, मुख्य आरक्षी विवेक बलियान, महिला आरक्षी श्वेता शर्मा तथा चाइल्डलाइन के सदस्य उपस्थित रहे।

पंजाब के किसानों का चंडीगढ़ कूच, सड़कों पर जाम, लोग परेशान; व्यवस्था संभालने में पुलिस के छूटे पसीने



चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में कूच किया है। पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। जाम में फँसकर लोग परेशान हुए। व्यवस्था संभालने में पुलिस के पसीने छूटे। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। किसानों सेक्टर-34 स्थित प्रदर्शनी ग्राउंड में महापड़ाव और विशाल रैली के लिए जुटे। दोपहर हो बजे तक किसान बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों में बैठकर आते रहे। चंडीगढ़ पहुंचने पर शराब के ठेकों पर किसानों की भीड़ लगी रही। वहीं, पुलिस को शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एड-वाइजरी जारी करनी पड़ी। शहर में कई रूट बदले गए। इससे लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ज्यादा सफर तय करना पड़ा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की अपील की। बसों में भरकर और उनकी छतों पर बैठकर किसान और उनके समर्थक चंडीगढ़ पहुंचे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने शहर में चौक-चौराहों पर घेराबंदी रखी।

लुधियाना अदालत की फाइल से गायब हुआ अहम दस्तावेज, हाई कोर्ट सख्त; 3 माह में जांच कर जिम्मेदार तय करने के आदेश



चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लुधियाना की एक सिविल अदालत के न्यायिक रिकार्ड से महत्वपूर्ण दस्तावेज की प्रति गायब होने के मामले को गंभीर मानते हुए तथ्यात्मक जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाया जाए कि दस्तावेज रिकार्ड से कैसे गायब हुआ और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अदालत ने लुधियाना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को तीन माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति लुधियाना जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस हर्ष बृंगर ने यह आदेश उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत वादी को संबंधित दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य अथवा मूल प्रति प्रस्तुत कर साबित करने की अनुमति दी गई थी। निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक रिकार्ड में सुरक्षित रखी गई दस्तावेज की फोटोकॉपी का गायब होना अलग और गंभीर विषय है। अदालत ने कहा, यह अब भी चिंता का विषय है कि संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी न्यायिक रिकार्ड से क्यों गायब है। इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिया, 'इस चूक की जांच आवश्यक है। इसलिए लुधियाना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस संबंध में तथ्यात्मक जांच कराएं, जिम्मेदार अधिकारी अथवा अधिकारियों की जवाबदेही तय करें और आज से तीन माह के भीतर रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को भेजें। गुरुद्वारे में गबन से जुड़ा है मामला मामला एक गुरुद्वारा द्वारा अपने पूर्व पदाधिकारी के खिलाफ 32 लाख रुपये से अधिक की वसूली के लिए दायर दीवानी वाद से जुड़ा है। वाद में दावा किया गया था कि गुरुद्वारा द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट में धन के बड़े पैमाने पर गबन का खुलासा हुआ था, जिसके आधार पर वसूली का मुकदमा दायर किया गया। सुनवाई के दौरान गुरुद्वारा ने आवेदन देकर बताया कि तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट न्यायिक फाइल से गायब हो गई है और उसे तलाशने के निर्देश दिए जाएं। निचली अदालत ने वादी को दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य या मूल प्रति से साबित करने की अनुमति देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दस्तावेज गायब होने की सूचना भेजने का निर्देश दिया था।

अदालती मामलों में जमा धन पर मिलेगा ब्याज, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; रकम एफडी में रखने का आदेश



चंडीगढ़। अदालतों में मामलों के निष्पादन (एजीक्यूशन) के दौरान जमा राशि अब निष्क्रिय नहीं पड़ी रहेगी, बल्कि इस पर ब्याज मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी निष्पादन अदालतों को निर्देश दिया है कि ऐसी प्रत्येक राशि को तत्काल किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाली सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में रखा जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत की प्रक्रिया के कारण किसी भी पक्ष को आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। जस्टिस पंकज जैन ने यह आदेश धन डिफेंसी से जुड़े एक निष्पादन मामले में दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका सफेदोद के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) द्वारा 11 मार्च 2025 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामलों में याचिकाकर्ता डिफेंसी धारक थे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह अदालत आवश्यक समझती है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सभी निष्पादन अदालतों को निर्देश दिया जाए कि निष्पादन कार्यवाही में प्राप्त राशि को निष्क्रिय रखने के बजाय तत्काल राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अदालत की कार्यवाही के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान न उठाना पड़े। जस्टिस जैन ने आदेश दिया कि निष्पादन कार्यवाही में जमा धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाए। फिक्स्ड डिपॉजिट संबंधित पात्र पक्ष को हस्तांतरित की जाए। संबंधित पक्ष चाहे तो ब्याज निकाल सकता है अथवा फिक्स्ड डिपॉजिट को जारी रख सकता है। अदालत ने कहा कि यदि धनराशि अदालत में बिना ब्याज के पड़ी रहती है तो बाद में इस अवधि के ब्याज को लेकर विवाद लगातार अदालतों को परेशान करते रहते हैं। इस संदर्भ में जस्टिस जैन ने टिप्पणी की, अन्यथा अदालत में जमा रहने की अवधि के ब्याज का भ्रष्टन लगातार अदालतों को परेशान करता रहेगा। अदालत की कार्यवाही किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं बननी चाहिए। फैसले में हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के के एल सुनेजा मामले का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही सभी अदालतों और न्यायिक मंचों को ऐसे दिशा-निर्देश बसाने का आदेश दे चुका है, जिनके तहत अदालतों या उनकी रजिस्ट्री में जमा धनराशि को बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जाए ताकि किसी भी पक्ष को भविष्य में आर्थिक हानि न हो। जस्टिस जैन ने आदेश दिया कि मामला आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

पंजाब सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा, ग्रेच्युटी व लीव इनकैशमेंट की गणना के लिए बढ़ाया काल्पनिक डीए

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) की गणना अब अधिक काल्पनिक (नोटेशनल) महंगाई भत्ते (डीए) के आधार पर की जाएगी। इससे पात्र कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का लाभ मिलेगा। यह



ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना मूल वेतन पर 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते को आधार मानकर की जा रही थी। हालांकि सरकार ने माना

कि ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ हैं और इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वह राशि

पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का किया पदार्पण, 11 आरोपी गिरफ्तार

फर्जी वेबसाइट, निवेश के नाम पर ठगी और फर्जी बैंक खातों का नेटवर्क उजागर, लाखों की बरामदगी

बिजनौर (सब का सपना):- ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत बिजनौर की स्पेसहा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाकर और निवेश के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चार लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 61 आधार कार्ड, 42 बैंक पासबुक, 33 डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नकदी सहित बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिएपॉर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण में इस गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि



आरोपी परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट की तर्ज पर bookkshrsplate.com और bookmyhsrp.com जैसी फर्जी वेबसाइट बनाकर हाई सर्क्युलरिटी नंबर प्लेट बुकिंग के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धनराशि वसूल रहे थे। इन खातों में ठगी की रकम मंगाकर बाद में उसे निकालकर गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस का कहना है कि वेबसाइट तैयार करने और उसे सफाई पोर्टल जैसा दिखाने के लिए चैट जीपीटी

सहित अन्य ए आई टूल्स और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ए आई टूल का उपयोग स्वयं अपराध नहीं है; बल्कि अपराध फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने से संबंधित है पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, एक टैबलेट, 16 मोबाइल फोन, फिंगरप्रिंट मशीन, 61 आधार कार्ड, 42 बैंक पासबुक, 33 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, 19 पेन कार्ड, 15 वॉटर आईडी, 10 चेकबुक, 12.20 लाख नकद तथा 88 हजार बैंक खातों में फ्रीज कराए हैं। कुल 2.08 लाख की धनराशि कार्यवाही के दायरे में लाई गई है। स्पेसहा पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य बैंक खातों और फरार सदस्यों की तलाश जारी है।

मालन नदी के तेज बहाव में व्यक्ति बहा, गोताखोरों की मांग तेज

रावली-ब्रह्मपुरी रपटे पर हादसा, ग्रामीणों की वेतावनी के बावजूद पार कर रहे थे रफ्टा

बिजनौर (सब का सपना):- लगातार हो रही बारिश के कारण उफनाई मालन नदी में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। हल्द्वी ब्लॉक के ग्राम कूकड़ा निवासी 43 वर्षीय रविंद्र पुत्र अतर सिंह तेज बहाव में बह गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी देर तक अपने स्तर पर उनकी तलाश की, लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार रविंद्र मंडावर थांना क्षेत्र के गांव शहजपुर में अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। रास्ते में रावली-ब्रह्मपुरी के बीच बने रपटे को पैदल पार करने का प्रयास किया। उस समय मालन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ था और



रपटे के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वहां मौजूद ग्रामीणों ने रविंद्र को कई बार रफ्टा पार न करने की सलाह दी और खतरे से आगाह किया। इसके बावजूद उन्होंने रफ्टा पार करने का प्रयास किया। इसी समय मालन नदी का दौरान तेज बहाव में उनका पैर

जाने तक प्रशासन की ओर से गोताखोरों की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। इससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने तत्काल प्रशिक्षित गोताखोरों तथा राहत-बचाव दल भेजने की मांग की। बताया गया कि यह घटना शाम लगभग चार बजे हुई। लगातार बारिश के कारण मालन नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र के रपटे और पुलिया अत्यंत जोखिमपूर्ण हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी, नालों और जलमग्न रपटों को पार न करने की अपील की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और रविंद्र की तलाश जारी है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द राहत एवं बचाव दल पहुंचकर सर्च अभियान को तेज करेगा।

पत्रकार प्रेस महासंघ में विकास शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी अध्यक्ष बनाए गए

पत्रकारिता और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिले में पत्रकारों ने जताई खुशी

बिजनौर (सब का सपना):- पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे चांदपुर निवासी वरिष्ठ पत्रकार विकास शर्मा को पत्रकार प्रेस महासंघ (दिल्ली) द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने उन्हें उत्तर प्रदेश पश्चिमी अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। इस मनोनयन के बाद पत्रकारों एवं शुभचिंतकों में खुशी की लहर है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। पत्रकार प्रेस महासंघ (पीपीएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा-निर्देश पर जारी मनोनयन पत्र में कहा गया है कि विकास शर्मा की कर्मठता, निष्ठा एवं पत्रकारिता के प्रति समर्पण को देखते



हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। संगठन ने उनसे अपेक्षा व्यक्त की है कि वे पत्रकार हितों की रक्षा, संगठन के विस्तार तथा समाजहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। मनोनयन पत्र के

अनुसार विकास शर्मा संगठन को अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ पत्रकारिता के मूल्यों को बढ़ावा देने, लेखन एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह मनोनयन

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पत्र की प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, सूचना निदेशक, जिलाधिकारी बिजनौर, पुलिस अधीक्षक बिजनौर तथा जिला सूचना अधिकारी को भी प्रेषित की गई है। विकास शर्मा के इस मनोनयन को जनपद बिजनौर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के लिए सम्मानजनक उपलब्धि माना जा रहा है।

पत्रकारों ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा पत्रकारों के अधिकारों और हितों की आवाज को नई मजबूती मिलेगी।

'सतलुज' फिल्म विवाद पर रवनीत बिट्टू ने साझा किए आंतकवाद के दौर के वीडियो, बोले- एक पहलू नहीं, पूरा सच जरूरी

अमृतसर। जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी पंजाबी फिल्म सतलुज पर रोक लगने के बाद से ही पंजाब का एक पुराना और दर्दनाक जख्म फिर से हरा हो गया। इस प्रतिबंध के बाद राज्य में आतंकवाद के उस दौर को लेकर राजनीतिक बहस चरम पर पहुंच गई है। जहां एक तरफ विपक्षी दल उस समय की सरकारों की भूमिका पर तीखे सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। रवनीत बिट्टू ने उस खौफनाक दौर की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिसने पूरे पंजाब की राजनीति में हलचल

मचा दी है। बिट्टू का साफ कहना है कि पंजाब के इतिहास को किसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने पूरा सच आना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कभी कोई इस पर भी फिलम बनाएगा। बिट्टू लगातार अपने इंटरनेट अकाउंट्स पर आतंकवाद के दौर की पोस्टरों को साझा कर रहे हैं। बम धमाके की वीडियो जारी कर मांगा जवाब पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने 80 व 90 के दशक में हुए खतरनाक रेडियो बम धमाकों का एक वीडियो साझा किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उस दौर में आतंकवादी सार्वजनिक जगहों पर रेडियो, ट्रांजिस्टर या बच्चों के



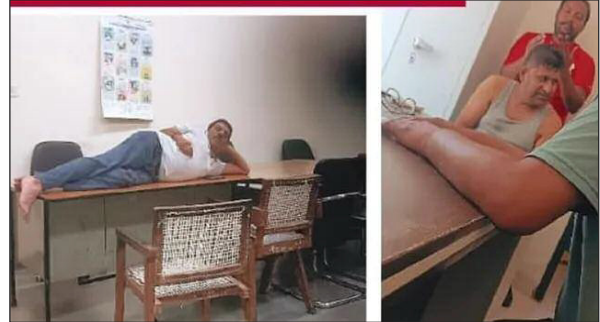
खिलौनों में बम छिपाकर रख देते थे। जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति या बच्चा उन्हें उठाता, धमनाक विस्फोट हो जाता था। इस तरह की कार्रवाया हरकतों से पूरे सूबे में खोफ फैलाया जाता था और शाम होते ही गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। इतिहास

का केवल एक पहलू नहीं, बल्कि पूरा सच जानना आवश्यक है। यह वह दर्द है जो पंजाब ने अपने निर्दोष लोगों की कुर्बानियों से सहा है। हर पीढ़ित को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। सच्ची शांति केवल सत्य के

नहीं मिल सकती, जो सामान्य परिस्थितियों में उन्हें प्राप्त होती। इसी की ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिसूचना में कहा है, यह देखते हुए कि ग्रेच्युटी और अवकाश के बदले नकद भुगतान सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले एकमुश्त लाभ हैं तथा एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्व अधिसूचना के कारण कम राशि मिली है, इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें यह लाभ देने का निर्णय लिया गया है। संशोधित डीए दरें और

समयबद्ध भुगतान नई व्यवस्था के अनुसार एक जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना मूल वेतन के 21 प्रतिशत डीए के आधार पर होगी। एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 24 प्रतिशत तथा एक जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 28 प्रतिशत डीए को आधार बनाया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है

चंडीगढ़ नगर निगम के दो कर्मचारी बर्खास्त, एक निलंबित; डयटी के दौरान गोशाला में कराते थे मसाज



चंडीगढ़। रायपुर कलां स्थित गोशाला में ड्यूटी के दौरान गोसेवक से मसाज और हाथ-पांव दबवाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम ने कड़ी कार्यवाही की है। नगर निगम ने सैनिटरी इंस्पेक्टर इंगू सिंगला और मल्टीटारकिंग वर्कर गौरव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही नियमित सैनिटरी जमादार सुच्चा सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में सैनिटरी इंस्पेक्टर और मल्टीटारकिंग वर्कर गोशाला परिसर में बेंच पर लेटे हुए गोसेवक से मसाज कराते दिखाई दे रहे थे। मामला सामने आने के बाद नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एसओएच) ने कार्यवाही के आदेश जारी किए। दोनों आउटसोर्स कर्मचारियों की एजेंसी को भी उनकी सेवाएं समाप्त करने की लिखित सूचना भेज दी गई है। गौरतलब है कि रायपुर कलां की यही गोशाला कुछ महीने पहले भी मृत गायों के शवों का ढेर मिलने के कारण सुर्खियों में रही थी। उस समय भी नगर निगम ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी। ताजा घटना के बाद एक बार फिर गोशाला के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों से गोशाला की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

जालंधर में बिस्त दोआब नहर फिर उफान पर, किनारा टूटते ही कॉलोनिनों में घुसा पानी; रातभर बचाव में जुटे रहे लोग



जालंधर। जालंधर में बिस्त दोआब नहर एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई। वीरवार देर रात गद्दपुर और कालिया कॉलोनी के पास नहर का किनारा टूटने से पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर फैलने लगा। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए खुद मोर्चा संभाल लिया और रेत व मिट्टी से भरी बोरेयों की मदद से पानी को कॉलोनिनों में घुसने से रोकने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर नहरी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 11 बजे नहर में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। तेज दबाव के कारण नहर का किनारा टूट गया और पानी आसपास के खाली प्लॉटों तथा निचले इलाकों की ओर बढ़ने लगा। पानी तेजी से रिहायशी क्षेत्र की तरफ बढ़ता देख इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। नहर के किनारे को मजबूत करने में जुटे मजदूर व लोग। खुद मिट्टी की बैरियां डाल रोका पानी स्थानीय लोगों ने प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद ही बचाव अभियान शुरू कर दिया। आसपास से रेत और मिट्टी से भरी बोरेयों लाकर टूटे हुए हिस्से पर लगाई गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने पानी का रुख कॉलोनिनों की ओर जाने से काफी हद तक रोक दिया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते यह प्रयास नहीं किया जाता तो कई घरों में पानी घुस सकता था। घटना की सूचना मिलने के बाद नहरी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। विभाग की टीम ने टूटे हुए हिस्से को बंद करने, पानी के बहाव को नियंत्रित करने और स्थिति सामान्य करने के लिए परम्पत कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। पहले भी कई बार लोग हो चुके परेशान इलाके के निवासियों का कहना है कि बिस्त दोआब नहर के ओवरफ्लो होने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इसी स्थान पर नहर का पानी रिहायशी क्षेत्रों की ओर फैल चुका है। हर बार लोगों को अपने स्तर पर बचाव करना पड़ता है, जिससे जान-माल का खराबना रहता है। निवासियों ने बताया कि इस बार भी कई खाली प्लॉट पानी से भर गए हैं और पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा था। उनका कहना है

मार्ग से ही प्राप्त होती है। बच्चों के सामने प्रिंसिपल को मारी थी गोली एक अन्य वीडियो में उन्होंने सरकारी स्कूल की बहादुर महिला प्रिंसिपल निर्मल कौता की तस्वीर साझा करते हुए चुनौती दी कि अगर किसी ने सच दिखाए तो किसी की हिम्मत है, तो इस दर्दनाक घटना पर फिल्म बनाकर दिखाए। बिट्टू ने दावा किया कि वर्ष 1990 में आतंकवादियों ने स्कूल परिसर के भीतर मामूम बच्चों के सामने इस प्रिंसिपल की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने गरीब बच्चों की भलाई के लिए आतंकवादियों द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड को लागू करने के लिए थोड़ा

समय मांग लिया था। इस मामूली बात पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन बख्तर खालसा ने उनकी जान ले ली। बिट्टू ने कहा कि ऐसी वीरंगना का बलिदान भी दुनिया के सामने आना जरूरी है। यूपी रोडवेज की बस, जिसे आतंकियों ने बम से उड़ाया था। हथियारों के साथ दिखाया आतंकियों का फोटोशूट एक अन्य पोस्ट में बिट्टू ने आतंकवाद के दौर की उन तस्वीरों को साझा किया, जिसमें आतंकियों को हथियारों के साथ दिखाया गया। बिट्टू ने बताया कि 90 के दशक में पंजाब ने आतंकवाद का वो खौफनाक दौर देखा, जिसने अनगिनत परिवारों को गहरे जख्म दिए।

ई-कॉमर्स के नाम पर साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल व सिम कार्ड बरामद



बुलन्दशहर (सब का सपना):- थाना डिबाई पुलिस ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लकड़ी की मूर्तियां बेचने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार एनसीआरपी (प्रतिबिंब) पोर्टल पर आरोपी के मोबाइल नंबर के विरुद्ध महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों से साइबर धोखाधड़ी की पांच शिकायतें दर्ज थीं। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद ग्राहकों को मूर्तियां नहीं भेजता था। इस मामले में थाना डिबाई पर बीएनएस एवं आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी विशाल निवासी डिबाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 1075 कारीगरों को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण व टूलकिट

बुलन्दशहर (सब का सपना):- उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर के लिए वर्ष 2026-27 में 1075 पारंपरिक कारीगरों को 10 दिवसीय निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण एवं उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में बढ़ई, नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची एवं धोबी वर्ग के कारीगर शामिल हैं। उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह ने बताया कि इच्छुक पात्र कारीगर 30 जुलाई 2026 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रतिभागियों को आरपीएल प्रमाणपत्र तथा उन्नत टूलकिट प्रदान की जाएगी। योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, बुलन्दशहर से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बुलंदशहर में प्रथम ऑटो का वितरण



बुलन्दशहर (सब का सपना):- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में लाभार्थी राजकुमार को पंजाब नेशनल बैंक, सालमपुर शाखा के वित्तीय सहयोग से एम/एस जय गोपाल ऑटो द्वारा जनपद का पहला ऑटो वाहन वितरित किया गया। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के मार्गदर्शन में ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को वाहन उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की प्रभावी पहल है। उन्होंने पात्र युवाओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक, सालमपुर शाखा एवं जय गोपाल ऑटो के प्रतिनिधियों ने भी लाभार्थी को शुभकामनाएं दीं।

दिल्ली एचसी ने डीयू को किया तलब, अदालत ने पूछा- शरणार्थी से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे?



नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। यह पिटीशन म्यांमार के एक रिफ्यूजी स्टूडेंट हेनरी हट्ट आंग लिन ने एडवोकेट अशोक अग्रवाल के जरिए फाइल की थी। इस पिटीशन में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए पासपोर्ट की शर्त की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जसमीत सिंह ने डीयू के वकील से पूछा कि आप एक रिफ्यूजी से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सोमवार तक का समय दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जुलाई रखी गई है।

अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, चेक बाउंस मामले में दिल्ली एचसी से मिला बड़ा झटका



नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेली लिमिटेड की ओर से दायर मामले में सुनाया। दिल्ली एचसी पहले सजा पर लगाई थी रोक अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा पूरा करने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया। इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी उन्हें इसी चेक बाउंस मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। क्योंकि उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाएगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेंडिप्लेशन सेंटर भी भेजा गया था। बार-बार अश्वासन, लेकिन भुगतान नहीं हालांकि, अदालत ने पाया कि राजपाल यादव ने बार-बार समय लेने और समझौते का आश्वासन देने के बावजूद तब रकम जमा नहीं कराई। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।

965 गाँवों तक पहुँचाए जिला पंचायत के विकास कार्य :- डॉ अंतुल तेवतिया

जनसेवा, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प के साथ बुलंदशहर ज़िला पंचायत ने ग्रामीण विकास को दी नई गति, पत्रकारों को सम्मानित कर मीडिया का जताया आभार

बुलन्दशहर (सब का सपना):- जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ अंतुल तेवतिया ने अपने पाँच वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अवसर केवल कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का नहीं, बल्कि जनसेवा, विकास और जनता के विश्वास की उस यात्रा को साझा करने का है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास" के संकल्प तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के

सुशासन, पारदर्शिता और अंत्योदय के मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में जिला पंचायत का एकमात्र उद्देश्य विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाना रहा, ताकि जनपद का कोई भी गाँव विकास से वंचित न रहे। ज़िला पंचायत ने केवल निर्माण कार्य ही नहीं कराए, बल्कि गाँवों को शहरों से, गाँवों को गाँवों से और लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया। सड़क, संपर्क मार्ग, आधारभूत सुविधाओं



तथा ग्रामीण संरचना को सुदृढ़ करना सर्वोच्च प्राथमिकता रही। जिला

पंचायत अध्यक्ष डॉ अंतुल तेवतिया ने बताया कि बुलंदशहर जनपद में

मजूरों सहित 951 ग्राम पंचायतें हैं। अत्यंत संतोष का विषय है कि ज़िला पंचायत के विकास कार्य 965 गाँवों तक पहुँच चुके हैं। जहाँ कुछ मजूरों में अभी कार्य शेष हैं, उन्हें आगामी कार्ययोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि जब तक विकास की अंतिम किरण अंतिम मजुरे तक नहीं पहुँचती, तब तक यह विकास यात्रा निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पाँच वर्षों की यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों,

कर्मचारियों, ज़िला पंचायत सदस्यों और सबसे बढ़कर बुलंदशहर की जागरूक जनता के सहयोग, विश्वास और सहभागिता का परिणाम है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ अंतुल तेवतिया ने मीडिया जगत् का विशेष आभार व्यक्त करते हुए

कहा कि मीडिया ने केवल समाचारों का प्रसारण ही नहीं किया, बल्कि जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर विकास कार्यों की अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जनकेंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

दिल्ली में माफिया का दुस्साहस, सरकारी जमीन पर कब्जा कर चलाई पार्किंग; नाले में गिरी कार

पूर्वी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग माफिया सरकारी अधिकारियों व सरकार और निगम पर हावी हैं। कबीर नगर क्षेत्र में कई माफिया ने मिलकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले के बराबर की जमीन पर अवैध कब्जा कर पार्किंग चला रहे हैं। जिस जगह पर पार्किंग बनाई है, वहां पर नाले की गंद पड़ी हुई है, जिसे समतल किया हुआ है। मंगलवार रात कार ठीक से खड़ी करने के चक्कर में पार्किंग का एक कर्मचारी मारुति की रियाज कार लेकर पास के सिंचाई विभाग के नाले में जा गिरा। पार्किंग के कर्मचारी अनस के खिलाफ केस दर्ज क्रेन के जरिये कार को नाले से निकाला गया। यह कार एक निजी कंपनी की है। यह कंपनी कृषि मंत्रालय में ठेके पर कार की सैवाएँ देती है। कार चालक राहिल की शिकायत पर



वेलकम थाना पुलिस ने पार्किंग के कर्मचारी अनस के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, दूसरे के जीवन को खतरे में डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। राहिल अपने परिवार के साथ कबीर नगर में रहता है। वह एक कंपनी में चालक है। वह कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को कार से ले आता और ले जाता है। राहिल ने पुलिस

को बताया वह मंगलवार रात को कार को अपने साथ कबीर नगर ले आया था। नाले के किनारे उसने पार्किंग देखी तो वहीं पर कार खड़ी कर दी। दावा किया कि चाबो भी उसने पार्किंग कर्मचारी अनस को दी। अगले दिन सुबह पार्किंग में गया तो देखा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पता चला कि पार्किंग का कर्मचारी कार लेकर नाले में जा गिरा था।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा के लिए एएपी चलाएगी देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, रविवार से होगी शुरूआत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। केंद्र सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी करने वालों को सख्त सजा दिलाना हर सनातन अनुयायी का कर्तव्य है।



हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, जिसमें देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी अपील दर्ज करेगा।ह्ज जापानी पार्क से होगी अभियान की शुरूआत केजरीवाल ने बताया कि इस अभियान की शुरूआत रविवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क

एएपी में सिर्फ विवाद ही मिले 16 पार्षदों के साथ मुकेश गोयल की इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय

नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में औपचारिक विलय हो गया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्टी के संयोजक मुकेश गोयल, हेमचंद गोयल समेत 16 पार्षदों का भाजपा में स्वागत किया। भाजपा सरकार बनने के बाद कामकाज में सुधार: हर्ष मल्होत्रा हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के महापौर रहने के बावजूद निगम के कामकाज से असंतुष्ट होकर मुकेश गोयल और हेमचंद गोयल के नेतृत्व में पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास

पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली नगर निगम में भाजपा का महापौर है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद निगम के कामकाज में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री निधि से प्रत्येक पार्षद को अपने-अपने वार्ड में विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नीतियों से प्रभावित होकर मुकेश गोयल ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने का फैसला किया है। उन्होंने सभी पार्षदों का पार्टी में स्वागत

किया। दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय: रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली और नगर निगम में भाजपा का शासन होने से राजधानी के विकास के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने दिल्ली के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से भाजपा में विलय का निर्णय लिया है। पिछले लगभग सवा साल से दिल्ली के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ

जिरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। आप में विकास की उम्मीद से गए थे: मुकेश गोयल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक मुकेश गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। इसी वजह से पार्टी ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वह इस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी में गए थे कि दिल्ली का विकास होगा, लेकिन दिल्ली और नगर निगम में आप के शासन के बावजूद विकास नहीं हो सका।



व्यवस्था चाहता है। वैनडाइन ने दिल्ली की पटयाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा के सामने अपनी समस्या रखकर यह मांग की है।कोर्ट को बताया कि जेल में मसालेदार और ऑयली, डीप-फ्राइड और चिकनाई वाला खाना मिलता है।

कहा कि वह ऐसा खाना नहीं खा सकता है। आतंकी साजिश और भारत-म्यांमार सीमा पर सक्रिय उग्रवादों संगठनों को सैन्य प्रशिक्षण देने के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद विशेष एनआईए अदालत ने वैनडाइन सहित सभी को यूएपीए के तहत 11 दिनों

अफगानिस्तान आदि में फिल्में बनाई। लीबिया गृहयुद्ध (2011): लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए शामिल हुआ। वह लीबिया में कैद रहा और छह महीने तक युद्धबंदी रहा। रिहाई के बाद वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चित हो गया। क्या है आरोप? पर्यटक वीजा पर भारत में प्रवेश कर मसौमे के प्रतिबंधित क्षेत्रों में गए। बिना परमिट के म्यांमार में अवैध प्रवेश। भारत में प्रतिबंधित कुछ विद्रोही समूहों को हथियार, ड्रोन और सैन्य/ड्रोन युद्ध प्रशिक्षण दिया। यूरोप से बड़ी संख्या में ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार भेजे गए



मैंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं आने दिया

अभिनेता और फिल्ममेकर कुणाल खेमू इन दिनों अपने नए रियलिटी शो 'अलायंस' को लेकर चर्चा में हैं। कुणाल ने हाल ही में उस सवाल का जवाब दिया, जो अक्सर उनसे पूछा जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का हिस्सा बनने के बाद क्या उन्हें कभी किसी तरह का दबाव या उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ? इस पर कुणाल ने कहा कि उन्होंने कभी भी निजी रिश्तों को अपने काम और कला के बीच नहीं आने दिया। बातचीत में सवाल का जवाब देते हुए कुणाल ने कहा, 'नहीं, मेरे लिए मेरी कला और मेरे भीतर का कलाकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही मेरे लिए सबसे अहम है। सच कहूँ तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं कि मैं शर्मिला टैगोर का दामाद हूँ।' अगर मैं यह कहूँ कि मैं इस बारे में सोचता हूँ या इससे बचने की कोशिश करता हूँ, तो यह झूठ होगा। यह बात मेरे दिमाग में रहती ही नहीं है। 'अभिनेता ने आगे कहा, 'मेरी क्रिएटिव जर्नी हमेशा एक्टिंग और फिल्ममेकिंग के प्रति मेरे पेशेन से प्रेरित रही है। मैंने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया कि मैं किस परिवार का हिस्सा हूँ। किसी कलाकार की असली पहचान उसके काम से बनती है, न कि उसके पारिवारिक रिश्तों से।' बता दें कि कुणाल खेमू ने अभिनेत्री सोहा अली खान से 25 जनवरी 2015 को शादी की थी। सोहा अली खान, दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की बेटी हैं।



जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है रणवीर सिंह की अगली फिल्म 'प्रलय'

'धुरंधर' की सफलता के बाद फैंस रणवीर सिंह की अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्ममेकर जय मेहता की जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है। साथ ही फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में शूट किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'प्रलय' की शूटिंग सितंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक स्रोत ने बताया, 'रणवीर 2026 के दूसरे हाफ में जय मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी और उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी है। फिल्म के बड़े पैमाने और जॉनर को देखते हुए इसके लिए जबरदस्त फिजिकल और इमोशनल तैयारी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, जहां जय मेहता और उनकी टीम उन टेक्नीशियन्स के साथ मिलकर काम कर रही है जो पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स प्रोडक्शन शुरू होने से पहले फिल्म की विशाल पोस्ट-एडिटिंग दुनिया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रलय' काफी हद तक विजुअल इफेक्ट्स पर निर्भर करेगी और राइटिंग टीम स्क्रीनले और फिल्म की बड़ी जॉम्बी दुनिया को बेहतर बनाने का काम जारी रखेगी।



कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ काम करने का काजल ने शेर किया अनुभव

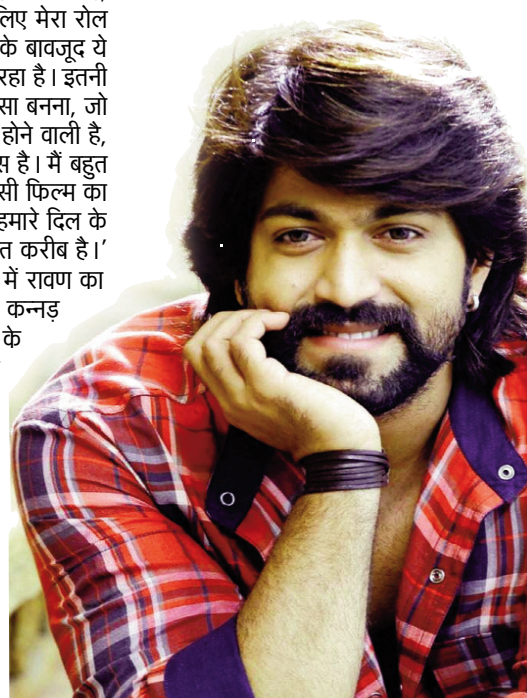
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में दिखेंगे। जहां फैंस इस बड़ी स्टारकास्ट को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं काजल ने खुलासा किया है कि फिल्म के पहले पार्ट में उनका रोल काफी छोटा है।

पहले पार्ट में लिमिटेड है काजल का रोल हाल ही में इंटरव्यू में काजल ने बताया कि पहले पार्ट में मंदोदरी का रोल ज्यादा नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि कहानी का बड़ा हिस्सा लंका से पहले का है, इसलिए उनके किरदार को शुरूआती हिस्से में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। काजल ने कहा, 'हमने अभी सिर्फ पार्ट 1 की शूटिंग की है और जाहिर है उसमें लंका का हिस्सा कम है, और मैं मंदोदरी हूँ। इसलिए मेरा रोल बहुत लिमिटेड है। इसके बावजूद ये अनुभव बहुत शानदार रहा है। इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनना, जो एक वर्ल्ड फिल्म होने वाली है, बहुत खास एहसास है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ, जो हमारे दिल के बहुत करीब है।'

काजल ने इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ काम करने का अनुभव भी शेर किया। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उनके काम की फैन रही हैं और उनके साथ काम करना शानदार रहा। उन्होंने कहा, 'वो बहुत अच्छे एक्टर

हैं। मैं हमेशा से उनके काम को पसंद करती आई हूँ और इस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो इस फिल्म को लेकर बहुत इन्वील्व हैं। वो बेहद प्रोफेशनल हैं और निश्चित तौर पर बहुत टैलेंटेड हैं।'

निवेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। अब तक मेकर्स ने फिल्म की सिर्फ एक झलक दिखाई है, जिसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आए। साथ ही रवि दुवे (लक्ष्मण), साई पल्लवी (सीता) और अयोध्या की भव्य दुनिया की झलक भी देखने को मिली।



महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए उम्मीद भरा दौर है

बीते दिन शुक्रवार को यश राज फिल्म्स के स्पार्ड युनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' रिलीज हुई, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी अहम भूमिकाओं में हैं। इसी के साथ हुमा कुरेशी अभिनीत 'बेबी डू डाई डू' ने भी दस्तक दी। दोनों फिल्मों के विलेज पर हाल ही में हुमा कुरेशी ने चुप्पी तोड़ी।

फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में हुमा कुरेशी ने एक मूक बांधर दिव्यांग का किरदार अदा किया है। इस भूमिका के लिए उनकी काफी तारीफ हो रही है। हाल ही में हुमा ने फिल्म पर बात की। हुमा ने कहा, 'मैं एक ऐसी महिला किरदार का रोल कर रही हूँ, जो सुन या बोल नहीं सकती। यह कोई कमी या कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में उसकी ताकत है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किरदार हमेशा पुरुष ही होता है। महिला प्रधान एक्शन फिल्मों के लिए बढ़ते स्पेस के बारे में बात करते हुए हुमा कुरेशी ने कहा कि दर्शकों की बदलती उम्मीदों और अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की वजह से, मौजूदा समय महिलाओं के नेतृत्व वाली एक्शन फिल्मों के लिए एक उम्मीद भरा दौर है। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे रहने वाले हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना

रही हैं। बातचीत के दौरान हुमा कुरेशी ने 'बेबी डू डाई डू' और 'अल्फा' के बॉक्स ऑफिस टकराव पर भी चुप्पी तोड़ी। हुमा ने दोनों महिला प्रधान फिल्मों के एक साथ आने का स्वागत किया। हुमा ने कहा, 'मैं 'अल्फा' को कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखती। मुझे लगता है कि हर तरह की फिल्में बनने और देखे जाने की गुंजाइश है। हमारी फिल्म इंडिपेंडेंटली बनी है। मैं यह भी नहीं देख रही कि उस वीकएंड और क्या रिलीज हो रहा है? बस अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहती हूँ। दूसरी ओर, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे दौर में हैं जहां बॉक्स ऑफिस पर दो महिला-प्रधान फिल्में टकरा रही हैं। हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां यह असंभव है।



मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी नहीं होगी 'हैवान'

सैफ अली खान और अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म 'हैवान' में एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर सैफ ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म 'हैवान' उनकी 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी बिल्कुल नहीं है। एक खबर के



अनुसार, सैफ ने बताया कि 'हैवान' में अक्षय कुमार एक खतरनाक विलेन के रोल में नजर आएंगे। सैफ उन्हें इस नए अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। सैफ ने अक्षय को अपने बड़े भाई जैसा बताया है। उनका कहना है कि दोनों की 30 साल पुरानी दोस्ती है, दोनों एक-दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और उनके बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। भले ही फिल्म 'हैवान' की कहानी बहुत गंभीर है, लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय और सैफ कैमरे के पीछे खूब मजाक-मस्ती करते थे। उनकी इन शरारतों को देखकर निर्देशक प्रियदर्शन उन्हें अक्सर बच्चों की तरह डांटते भी थे। 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसी पिछली फिल्मों में दोनों ने दर्शकों को खूब हंसाया था। लेकिन सैफ ने साफ किया है कि 'हैवान' कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर कहानी पर आधारित है। आखिर में सैफ ने कहा कि अगर भविष्य में कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली, तो वह अक्षय के साथ फिर से कोई कॉमेडी फिल्म जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को 'हैवान' में इन दोनों का एक बिल्कुल अलग और रोमांचक अंदाज देखने को मिलेगा। 'हैवान' का निर्देशक प्रियदर्शन कर रहे हैं। यह एक थ्रिलर फिल्म है। 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान साथ नजर आएंगे।

आज हर वो शख्स क्रिएटर है, जिसके पास फोन है



पिछले दिनों अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स की भूमिका में तारीफें बटोरने वाली कंगना इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं रिएलिटी शो 'लॉकअप' को लेकर। उनकी 'क्वीन 2' को लेकर भी खबरें हैं कि वो फिल्म पूरी हो चुकी है। अपनी भूमिकाओं में जान डाल देने वाली यह अभिनेत्री पॉलिटिशियन के रूप में भी धाकड़ हैं। हिमाचल की रहने वाली कंगना जब छोटी उम्र में घर वालों की खिलाफत करके दिल्ली आई, तब तक उनके लिए अभिनेत्री बनने का रास्ता बहुत मुश्किल रहा। मगर पहले गैंगस्टर, फिर तनु वेडस मनु और क्वीन ने उन्हें अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। कई खड़े-मीठे अनुभवों से गुजरी कंगना अपने जीवन की उपलब्धियों में कई लोगों के योगदान की बात करती हैं। कंगना का मानना है कि अपने अकेले दम पर कोई भी इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। वे कहती हैं, 'इंसान की जिंदगी में कई लोग होते हैं, जो किस्मत को संवारते हैं। माता, पिता, गुरु से शुरू होने वाला ये सिलसिला चलता जाता है। आज जो शब्दावली में बोल भी पा रही हूँ, तो उसमें कई लोगों का योगदान है। जब मैं अभिनय के क्षेत्र में आई, उस वक़्त अनुराग बसु मेरे

करियर में अहम साबित हुए, जिन्होंने मुझे गैंगस्टर जैसी फिल्म दी और फिर विकास बहल इसे फिल्मकार जिन्होंने वहीन से मुझे सफलता दिलाई। पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री पर रस्ते डाउन के बादल मंडरा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फिल्मों का बजट, स्टार्स की फीस जैसे फैक्टर्स में यदि सुधार नहीं हुआ, तो फिल्म उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। इस पर कंगना कहती हैं, 'फिल्म इंडस्ट्री को उठाना तो पड़ेगा ही।

मुझे याद है, आज से दस साल पहले मैं और शेखर कपूर (फिल्मकार) किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, कंगना जिसके हाथ में कैमरा या मोबाइल होगा, वो एक फिल्म बनाएगा। उस वक़्त मुझे लगा था कि हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। मुझे उनकी बात गंजी नहीं थी। मगर आज देखिए, आज इंटरनेट पर लोग दो-दो मिनट की फिल्म बना रहे हैं। कोई ट्रैन में चढ़ा हुआ है, तो कोई दूर -

दराज के गांव में बैठी कोई महिला दुध दुहना सिखा रही है, कोई खाना पकाना सिखा रहा है, तो कोई मेकअप टिप्स दे रहा है और आप सभी इस सिस्टम में पूरी तरह से एंगेज हो गए हैं। दूसरों की क्या कहूँ, मेरे खुद के माता-पिता आज रील्स में इतना बिजी हैं। आज रिलेटेबल रोल्स खत्म होते जा रहे हैं। पुष्पा जैसा मजदूर आपने कब देखा था? शायद अभिताम बच्चन जी के दौर में।'

जॉन सर सही मायनों में कूल हैं

कंगना की नई फिल्म को लेकर एक दिलचस्प बात ये है कि इसका शीर्षक जॉन अब्राहम के पास रजिस्टर था, मगर उन्होंने खुशी-खुशी इसे कंगना को दे दिया। इस पर कंगना कहती हैं, 'इंसान वहीं मांगता है, जहां उसे उम्मीद होती है। जॉन सर के साथ शूटआउट एट वडाला की थी। उनके बारे में जो कहा जाता है कि वे अपने काम से काम रखते हैं और सही मायनों में कूल गाय हैं। उनके साथ एक कमल का कफर्ट था। मैं इसे दोस्ती तो नहीं कहूँगी, क्योंकि दोस्ती की अलग-अलग परिभाषा होती है। जो मैंने उनका बर्ताव देखा, तो पाया कि वे अपने काम से काम रखते हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि दुनिया-जहान से ला-ताल्लुक हैं। अप्रोचेबल हैं, रीवेबल हैं,, अगर हैं अपनी दुनिया में। मैंने जब भी उनके साथ काम, किया, मुझे बहुत मजा आया। हमारी इस फिल्म का नाम पहले नर्स ऑफ कामा था, मगर शीर्षक में वो बात नहीं आ पा रही थी। तब टाइटल आया, भारत भाग्य विधाता, मगर फिर पता चला कि ये शीर्षक तो जॉन सर के पास है। जाहिर है, वो निर्माता भी हैं, तो एक निर्माता कई सालों तक पैसे जमा कर करके अपने टाइटल को सुरक्षित रखता है। मुझे लगा मैं इस शीर्षक के लिए किसी तरह से उन्हें मना ही लूँगी, मगर उसकी नौबत नहीं आई। मेरे कहने भर से उन्होंने मुझे दे दिया। उनका दिल बहुत बड़ा है।'

